श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 1 वर्ष, अंक 44, पृष्ठ 4, मूल्य 1.00

अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज शनिवार, 19 सितम्बर, 2020

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई की तैयारी सिर्फ कागजों पर, खड़ा नहीं किया गया सप्लाई चेन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने साधा मौन

नीलू रंजन, नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए टेस्टिंग किट, पीपीई किट, कोविड अस्पतालों की बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय की सांस ऑक्सीजन ने फुला दी है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उत्पादन क्षमता के बावजूद अस्पतालों तक उनकी आपूर्ति करने का सिस्टम गायब है। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इस संबंध में उठ रहे सवालों के जवाब में चुप्पी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को खपत की तुलना में अतिरिक्त 1900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का दावा किया था। यही सही भी है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आल इंडिया इंडस्ट्रीयल गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AIIGMA) की ओर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे सात राज्यों में सुचारू मेडिकल आक्सीजन सप्लाई के लिए तैनात नोडल अधिकारी अनिर्बन सेन भी मानते हैं कि लिक्विड मेडिकल आक्सीजन के उत्पादन की कोई समस्या नहीं है। समस्या लिक्विड ऑक्सीजन को फिलिंग स्टेशन तक ले जाने और उसे सिलेंडर में भरकर कोरोना के अस्पतालों तक पहुंचाने की है। अनिर्बन सेन के अनुसार जुलाई के बाद कोरोना का संक्रमण ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैला है और टीयर-दो और टीयर तीन शहरों से कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग उसी अनुपात में बढ़ गई है। लेकिन इन शहरों तक लिक्विड आक्सीजन पहुंचाने के लिए न तो पर्याप्त संख्या में टैंकर है और न ही उसे सिलेंडर में भरने का सिस्टम मौजूद है। ऐसे में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा है। जाहिर है कुछ राज्यों की ओर से आक्सीजन की दूसरे राज्यों सप्लाई रोकना समस्या का समाधान नहीं है। यही कारण है कि बड़े अस्पतालों में यह समस्या नहीं है। दिल्ली एनसीआर के यशोदा अस्पताल के एमडी पीएन अरोड़ा इस संबंध में पूछे जाने पर साफ कहते हैं कि आक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्हें आक्सीजन मिलने में भी समस्या नहीं आ रही है। लेकिन छोटे शहरों या बड़े शहरों के भी छोटे निजी अस्पतालों में समस्या खड़ी हो रही है।

ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राज्यों की सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है। लेकिन इस कंट्रोल रूम के कामकाज के बारे में वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। दैनिक जागरण ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता मनीषा वर्मा से जानना चाहा कि सरकार आक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकरो व सिलेंडर की आपूर्ति और उसके फिलिंग की प्रणाली लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है? विभिन्न राज्यों ने आक्सीजन की मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है और इसके लिए राज्य सरकारें केंद्र से किस तरह सहायता की मांग की है? लेकिन मंत्रालय में चुप्पी है। कोरोना मरीजों की मेडिकल आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व औद्योगिक संव?र्द्धन विभाग के सचिव गुरूप्रसाद महापात्रा भी आक्सीजन की कमी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध हुए।

सरकार को ऑक्सीजन की बड़े पैमाने पर जरूरत का अंदाजा था। 24 मार्च से पूरे देश में कड़े लॉकडाउन की घोषणा के अगले दिन ही 25 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बाद ही ऑक्सीजन के उत्पादन और अबाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिख दिया। इसके 10 दिन बाद ही चार अप्रैल को आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संवर्द्धन विभाग के सचिव गुरूप्रसाद महापात्रा की अध्यक्षता में नौ सदस्यी कमेटी का गठन किया। इसके दो दिन बाद छह मार्च को गृह सचिव ने एक बार फिर आक्सीजन को जरूरी दवा बताते हुए इसकी सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा। सात अप्रैल को औद्योगिक ऑक्सीजन उत्पादकों को मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन की अनुमति दे दी गई। 18 अप्रैल को पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) ने लिक्विड आक्सीजन उत्पादन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर लांच किया। इसके बाद 22 अप्रैल को आक्सीजन के बढ़ते खपत को देखते हुए पेसो ने नाइट्रोजन, अर्गोन, हेलियम और औद्योगिक आक्सीजन सिलेंडर के मेडिकल आक्सीजन सिलेंडर में बदलने का एसओपी जारी किया।

ऑक्सीजन की कालाबाजारी की शिकायतें

इन सारी तैयारियों के बावजूद जुलाई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की कालाबाजारी की शिकायतें आनी शुरू हो गई। इसे रोकने के लिए 24 जुलाई को अनधिकृत व्यक्ति के लिए खाली सिलेंडर में आक्सीजन भरवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी दिन आक्सीजन उत्पादकों, उसे सिलेंडर में भरने वाले और भरे हुए सिलेंडर का स्टॉक रखने वाली सभी कंपनियों के लिए प्रतिदिन का डाटा रखना अनिवार्य कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए टैंकर, सिलेंडर और उसके फिलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। जाहिर समस्या बढ़ती चली गई। आखिरकार 17 अगस्त को पेसो ने लिक्विड नाइट्रोजन ढोने वाले टैंकरों को ऑक्सीजन ढोने की अनुमति दी। लेकिन इससे भी अस्पतालों तक आक्सीजन की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी। आक्सीजन की कमी के राजनीतिक मुद्दा बनते देख महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने इसके दूसरे राज्यों में भेजने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और मामला अदालत तक जा पहुंचा। लेकिन जिसे इस पर निगरानी रखनी है वह चुप है।

राष्ट्रपति कोविंद की आज सालाना विजिटर कांफ्रेंस में होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल पर चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तेजी से अमल को लेकर जुटी सरकार के साथ राष्ट्रपति भी पूरी ताकत से जुट गए है। यही वजह है कि राष्ट्रपति की अगुवाई में शनिवार यानी 19 सितंबर को सालाना होने वाली विजिटर कांफ्रेंस का विषय भी इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अमल ही रखा गया है। दिन भर चलने वाले इस बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। साथ ही वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष संस्थानों के मुखिया के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही उनकी राय भी जानेंगे। खासबात यह है कि पिछले पंद्रह दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर यह दूसरी बड़ी बैठक है, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने सात सितंबर को देश भर के राज्यपालों, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षाविदों के सम्मेलन को भी संबोधित किया था।

देश के आठ समुद्री तटों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का दर्जा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। समुद्री तटों को पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने को लेकर छिड़ी मुहिम के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने देश के आठ समुद्री तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग के दर्जे में शामिल करने की सिफारिश की है। यह दर्जा उन्हीं समुद्री तटों को मिलता है, जो साफ-सुथरे होने के साथ हर तरह से सुरक्षित होते है। साथ ही उनका रखरखाव और प्रबंधन भी बेहतर होता है। जिनकी सिफारिश की गई है, उनमें गुजरात के शिवराजपुर, ओडिशा का गोल्डन तट, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का रुशीकोंडा,

कर्नाटक का पदुबिद्री और कसरकोद के साथ अंडमान एवं निकोबार और दमन-दीव के एक-एक तट है। अब तक देश के एक भी तट को यह दर्जा प्राप्त नहीं है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को विश्व कोस्टल दिवस पर इसकी घोषणा की। यह दिवस फिलहाल दुनिया के सौ देशों में मनाया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में समुद्री तटों को स्वच्छ रखने की मुहिम तेज की गई है। आने वाले चार सालों में देश के करीब सौ समुद्री तटों को भी चमकाया जाएगा। जहां स्वच्छता और प्रबंधन को लेकर विशेष मुहिम चलाई जाएगी। मंत्रालय इन सभी समुद्री तटों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर संवारने की योजना पर काम कर रही है।

भारत और चीन के बीच हो सकती है कोर कमांडर स्तर की बातचीत

नई दिल्ली, एएनआइ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर भारत और चीन के बीच दो-तीन दिनों में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, इस बैठक में भारतीय पक्ष की ओर से कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे इसको लेकर एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में बातचीत के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बातचीत में भारत एलएसी के दूसरी ओर से चीनी सैनिकों की वापसी को लेकर दबाव बनाएगा।

सनद रहे कि अब तक हुई सैन्य स्तर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है।

एलएसी से सटे इलाकों में भारत और चीन की सेनाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल, बातचीत के दौरान चीन सीमा पर शांति कायम करने की बात तो करता है लेकिन अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाता। चीनी सेना के अड़ियल रुख को देखते हुए भारतीय सेना ने भी पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के सीजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में यदि चीन कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई करता है तो उसे भारतीय जवानों की ओर से करारा जवाब मिलेगा।

विदेश मंत्रालय भी साफ शब्दों में कह चुका है कि पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी बिंदुओं से चीन को अपनी सेना को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। चीन को सीमा पर एकतरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल गुरुवार को कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने पिछले तीन हफ्ते में पैंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों पर तीन बार उकसावे वाली हरकतें की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर 45 साल में पहली बार गोलियां चली हैं।

छात्रों को बीई-बीटेक में प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेंगे संस्थान

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इंजीनियरिंग और तकनीक जैसे विषयों में डिप्लोमा किए छात्रों को अब लेटरल इंट्री से बीई (बैचलर आफ इंजीनियरिंग) या बीटेक (बैचलर आफ टेक्नालाजी) जैसे अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सों में आसानी से प्रवेश मिल सकेंगे। कोई भी तकनीकी संस्थान इन छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसे लेकर पहले से प्रचलित नियमों को और सख्त कर दिया है। साथ ही सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को इसका सख्ती से अमल कराने के निर्देश भी दिए है।

एआईसीटीई के नियमों के तहत फिलहाल सभी तकनीकी संस्थानों

को डिप्लोमाधारी छात्रों को बीई या बीटेक जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में लेटरल इंट्री के जरिए प्रवेश देने का प्रावधान है। इसके तहत इन छात्रों को सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर तकनीकी संस्थान इन छात्रों को प्रवेश देने से इंकार कर देते थे।

संस्थानों के इस रवैए से डिप्लोमा धारी यह छात्र लंबे समय से परेशान थे। हाल ही में एआईसीटीई ने इस छात्रों की समस्याओं को समझा और इसका उचित निराकरण किया है। इसके तहत लेटरल इंट्री के प्रवेश के नियमों को और सख्त करते हुए इसे प्रवेश नियमों को लेकर संस्थान की तैयार होने वाली हैंडबुक में जगह दे दी है। जिसे अब प्रत्येक तकनीकी संस्थान के लिए मानना अनिवार्य होगा। खाली पड़ी सीटों पर इन छात्रों को प्रवेश देना ही होगा। एआईसीटीई ने इसके साथ ही सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भी निर्देश किया है, वह अपने अधीन सभी संस्थानों में इसे सुनिश्चित कराने के दिशा-निर्देश दे। साथ ही कहा है कि यदि कोई संस्थान इसे मानने से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जाएगी।

इसके साथ ही ही बीई और बीटेक में लेटरल इंट्री से प्रवेश से जुड़े नियमों को एक बार फिर से स्पष्ट किया है। जिसमें कहा कि 45 फीसद (आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसद) से ज्यादा अंक पाने वाले डिप्लोमा धारी छात्र इसके लिए पात्र होंगे। वह इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से हो सकते है। इसी तरह बीएससी पास छात्र जिनके अंक 45 फीसद से ज्यादा है, वह भी इनमें प्रवेश के लिए पात्र होंगे। बशर्ते उनका बारहवीं में गणित होना जरूरी होगा।

एम्स ने कहा, अगले साल के मध्य तक कोरोना वैक्सीन के आने की संभावना, तब तक बचाव ही उपाय

नई दिल्ली, एएनआइ। एम्स ने शुक्रवार को कहा कि देश में विभिन्न जगहों पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इसमें 600 से अधिक वालंटियर्स शामिल हैं। नई दिल?ली स्थित एम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. संजय राय ने कहा कि यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो कोई भी वैक्सीन अगले साल के मध्य तक दुनिया में कहीं भी आ जाएगी। ऐसे में अगले साल के मध्य तक ही स्थिति सामान्य होने की संभावना है।

उल्होंने कहा कि जब तक इस महामारी से बचाव का कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं होता है तब तक निवारक उपाय जैसे मास्क, हाथ की सफाई आदि का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। डॉ. राय ने यह भी बताया कि अप्रैल-मई में आयोजित किए गए क्टफके सेरोसर्वे में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 64 लाख वयस्क संक्रमित पाए गए थे। सेरो-सर्वेक्षण केवल संक्रमण की दिशा को दशार्ता है जबकि परीक्षण से संक्रमण की वास्तविक संख्या पता चलती है।

वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार तक 41,12,551 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। मौजूदा वक्त में देश में रिकवरी रेट 78.86 फीसद पर पहुंच गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,14,677 हो गई है जबकि गत 24 घंटे में 1,174 और लोगों की मौत के साथ अबतक 84,372 लोगों की मौत इस बीमारी के चलते हुई है। हालांकि महामारी से होने वाले मौतों की दर में और गिरावट आई है और यह 1.62 फीसद पर सिमट गई है। मौजूदा वक्त में देशभर में 10,17,754 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया कि भारत में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक छह करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। 16 सितंबर तक देश में 6,05,65,728 नमूनों की जांच की गई। बीते 28 अगस्त तक 4,04,06,609 नमूनों की जांच की गई थी। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में पिछले 20 दिन में औसतन प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोगों की जांच हुई है। दो करोड़ नमूनों की जांच बीते 20 दिनों में ही की गई है।

सुशांत केस में NCB का बड़ा एक्शन 4 और ड्रग पैडलर गिरफ्तार

मुंबई, एजेंसी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम पूरे एक्शन में है। इस केस में रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा समेत कई लोगों पर शिकंजा कसने के लिए एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने मुंबई से चार और ड्रग पैडलर्स को भी हिरासत में लिया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के ड्रग पैडलर राहिल विश्राम को 1 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। एनसीबी ने उसके पास से 4.5 लाख रुपये नकद भी जब्त किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर ने बताया कि राहिल का सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से संबंधित अन्य पैडलर्स से सीधा संपर्क है। वहीं, सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मौत से पहले दिशा ने 100 नंबर पर कॉल किया था। जिसपर मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आया है। पुलिस के एक अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि दिशा सालियन के फोन से आखिरी कॉल उनकी दोस्त अंकिता को की गई थी। उसके आखिरी बार 100 नंबर डायल करने का जो दावा किया जा रहा है, वह गलत है। दिशा सालियन 8 जून को मुंबई में मृत पाई गई थी।

इससे पहले एनसीबी सुशांत केस में ड्रग से जुड़े दो और लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमे से एक शौविक का दोस्त जयदीप मल्होत्रा है, जिसे 18 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में सौंप दिया गया है। जबकि एनसीबी की टीम ने गोवा में छापा मारकर क्रिस कोस्टा को दबोचा। मुंबई लाकर उसकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी कराई गई। उसे 17 तक एनसीबी के हवाले किया गया है। इन दोनों को मिलाकर एनसीबी इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मीडिया को समूचे समुदाय को निशाना बनाने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी से उसके कार्यक्रम 'बिंदास बोल' पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मीडिया को एक समूचे समुदाय को निशाना बनाने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि चैनल को स्टोरी ब्रेक करने की इजाजत है लेकिन वह पूरे समुदाय पर ठप्पा नहीं लगा सकता है और ऐसी स्टोरी करके उन्हें पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं कर सकता है। सर्वोच्च अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन जकत फाउंडेशन को सुदर्शन टीवी के मामले में अपना पक्ष रखने को भी कहा है। चूंकि सुदर्शन टीवी ने इस एनजीओ पर सिविल सेवाओं में बड़े पैमाने पर मुसलमानों को प्रशिक्षण देने का अभियान छेड़कर 'यूपीएससी जेहाद' छेड़ने का आरोप लगाया है। सुदर्शन टीवी का आरोप है कि इस काम के लिए जकत फाउंडेशन को कुछ विदेशी आतंकी संगठनों से फंडिंग हो रही है।

जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर आपत्ति करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक असल मुद्दा है। आप जब भी उन्हें सिविल सेवा से जुड़ते हुए दिखाते हैं, आप आतंकी संगठन आइएस को दिखाते हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का सिविल सेवा में शामिल होना जैसे किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो। क्या मीडिया को पूरे समुदाय पर मुहर लगाने की इजाजत दी जा सकती है।

इससे पूर्व, सुदर्शन टीवी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर उस याचिका पर सुनवाई का सजीव प्रसारण कराने का अनुरोध किया जिसमें उसके कार्यक्रम 'बिंदास बोल' के खिलाफ शिकायत की गई है। इस कार्यक्रम के सामने आए प्रोमो में दावा किया गया है कि 'वह सरकारी सेवा में मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश' को उजागर करेगा।

खंडपीठ ने जकत फाउंडेशन की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े से कहा कि सुदर्शन टीवी ने उनके मुवक्किल के खिलाफ विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए हैं। इस पर हेगड़े ने कहा कि उनका मुवक्किल एक चैरिटेबल संस्था है और वह अपनी समाज सेवा में गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मदद करते हैं। यह इस तरह का काम है जो सरकारी अमले में भी होते नहीं देखा जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हेगड़े को बताया कि टीवी चैनल ने कुछ फॉरेन कॉट्रिब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट (एफसीआरए) रिकार्ड विदेशी फंडिंग के आरोपों के संबंध में दाखिल किए हैं। और अब यह जकत फाउंडेशन पर निर्भर करता है कि इस मामले में दखल देना चाहेंगे या नहीं। इस पर हेगड़े ने कहा कि जकत फाउंडेशन कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं चलाता है, बल्कि आइएएस की कोचिंग क्लासेज के लिए केवल फीस का भुगतान करता है। इससे पहले, शुक्रवार को हलफनामा के जरिये दाखिल जवाब में अदालत ने अपने कथित कार्यक्रम प्रशासनिक सेवा में मुस्लिमों की घुसपैठ का बचाव किया है। चैनल ने कहा कि यह उनके प्रवेश के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद से संबंधित विभिन्न संगठनों से चंदा लेने वाले जकात फाउंडेशन से प्राप्त सूचना के आधार पर उसने 'यूपीएससी जेहाद' शब्द का इस्तेमाल किया है।

गौरतलब है कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक चैनल के 'बिंदास बोल' के एपिसोड का प्रसारण करने पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा कि प्रथमदृष्टया लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। सुदर्शन न्यूज चैनल की ओर से निदेशक और संपादक सुरेश चव्हाण के जरिये दाखिल आवेदन में कहा, 'यह सम्मानपूर्वक बताया गया कि वर्तमान मामला जनता के विषय में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) द्वारा संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न इसमें शामिल है।' आवेदन में कहा गया कि चैनल के करोड़ों दर्शक कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं और पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और बहस के बिंदुओं को सुनना चाहते हैं।

सीएम योगी बोले- तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया, छह माह में नियुक्ति पत्र

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी के बीच में सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। कोरोना आपदा के कारण गहराए रोजगार के संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों पर तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को अगले छह महीने में नियुक्ति पत्र थमाने को भी कहा गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले तीन महीने में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और अगले छह महीनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बीते साढ़े तीन वर्ष में संपन्न तीन लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप तीन माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करें। इसके साथ ही छह महीने में सभी पात्रों को नियुक्ति पत्र

वितरित करें।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्ती हुई हैं, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे की भी सभी भर्ती कराई जाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकड़े कल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता ही हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्ड के साथ ही आयोग के साथ बैठक करने की योजना बना ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर को प्रदेश के सभी भर्ती बोर्ड व आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रुकी हुई नियुक्तियों के सम्बंध में वार्ता करेंगे। इस दौरान रुकी भर्ती कैसे फिर से शुरू हो और किस-किस विभाग में तत्काल पदों की जरूरत है, इस बात पर भी चर्चा होगी। 21 को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाली बैठक को लेकर सभी भर्ती बोर्ड व आयोग के अफसर मुस्तैद हो गए हैं। यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकाय सीमा में शामिल की गईं ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय किया है। ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा और पुलिस विभागों में कुल 85,629 पदों पर भर्तियों के लिए कार्यवाही चल रही है। इनमें से बेसिक शिक्षा विभाग में 69 हजार शिक्षकों तथा पुलिस विभाग में 16,629 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

ग्रामीण अंचल

प्रयागराज शनिवार, 19 सितम्बर, 2020

संक्षेप समाचार

मोबाइल छीन कर फरार हुए बदमाश

नैनी। कोतवाली क्षेत्र के रामनगर चौराहे के समीप शुक्रवार को बाइक सवार दो बदमाश एक दुकानदार का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटित वारदात की जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक नैनी कोतवाली क्षेत्र के राम नगर चौराहे के समीप रहने वाले अभिषेक केशरवानी शुक्रवार सुबह चौफटका रेलवे फाटक स्थित अपनी दुकान पर जाने के लिए घर के बाहर बाइक लेकर खड़े थे। तभी बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश पहुंचे और झपट्टा मारते ही उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए।

जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

नैनी। औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कला ग्राम सभा के फुलवरिया बस्ती के रहने वाला एक लगभग 25 वर्षीय युवक बीते कुछ दिन पूर्व जहरीला पदार्थ निगल लिया। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। जिससे परिजनों में कोहराम मच गया।

नौकरी में संविदा की अनिवार्यता को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा : उपमुख्यमंत्री

प्रयागराज। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कहा कि विपक्ष पांच साल संविदा पर नौकरी की अनिवार्यता पर भ्रम फैला रहा है। शासन द्वारा ऐसा कोई नियम पारित नहीं हुआ है।

प्रयागराज आये उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में पहले जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उसके निवारण हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पांच साल संविदा पर नौकरी की अनिवार्यता को लेकर भ्रम फैला रहा है। जबकि शासन के द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता झूठी अफवाह को लेकर सतर्क रहें और समाज के बीच जाकर विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे इस साजिश भरे अफवाह का पदार्फाश करें। बैठक में विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, संजय गुप्ता, डॉ. आरके वर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी, अवधेश चंद गुप्ता, शशि वार्ष्णेय, कुंज बिहारी मिश्रा, अरुण अग्रवाल, वरुण केसरवानी, राजेश केसरवानी, रमेश पासी, बबलू केसरवानी, विवेक अग्रवाल, विश्वास श्रीवास्तव, देवेंद्र प्रताप सिंह, मनीष केसरवानी, प्रमोद जायसवाल, किशोरी लाल जायसवाल, पार्षद मनोज कुशवाहा, विजय श्रीवास्तव, राजू पाठक आदि कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

सर्किट हाउस में बैठक को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री

गया था पत्नी को बुलाने नदी में मिली लाश

पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दी हत्या की तहरीर

शव मिलने के बाद रोते बिलखते परिजन

शंकरगढ़। पत्नी को बुलाने ससुराल गए युवक का शव शुक्रवार की सुबह टोंस नदी में पाया गया। नदी में शव मिलने की जानकारी होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चीरघर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र के लवायन कला निवासी कामता प्रसाद (32) पुत्र बनारसी लाल की ससुराल खीरी में है। बताया जाता है कि कामता की पत्नी पिछले कई महीने से अपने मायके में रह रही है। मायके पक्ष की मानें तो कामता, पत्नी के साथ मारपीट करता था। इसी से नाराज पत्नी उषा मायके में रहने लगी। दूसरी तरफ कामता के पिता बनारसी लाल का कहना है कि उनका बेटा, पत्नी उषा को बुलाने के लिए गुरुवार को ससुराल गया था। ससुरालियों ने कामता की मार-पीटकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। शुक्रवार को नारीबारी पुलिस चौकी क्षेत्र के छतरगढ़ गांव के समीप टोंस नदी में एक युवक का शव उतराता मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कामता प्रसाद निषाद के रूप में की। एसओ शंकरगढ़ राजेश उपाध्याय और नारीबारी चौकी प्रभारी जगदीश कुमार की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मृतक के पिता बनारसी लाल की तहरीर पर साले, पत्नी उषा सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण स्पष्ट हो जाएगा।

46 की कोरोना जाच दो पाजटिव

करछना। शुक्रवार को सीएचसी करछना मे 46 लोगो की कोरोना जाच की गई जिसमे दो लोगो की रिर्पोट पाजटिव आई। अधीक्षक डाद जीके तिवारी ने बताया कि आज हुई जाच के दौरान हथिगन और कपठुआ गांव के एक.एक लोग पाजटिव मिले है।उन्होने सभी से महामारी के प्रति सामधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि लगातार सक्रमण बढ रहा है किन्तु लोग इसके प्रति बेपरवाह नजर आ रहे है।

झूठी एफआईआर दर्ज कराकर फंसाने की साजिश, जांच की मांग

प्रयागराज। भाजपा नेता डॉ. श्याम प्रकाश द्विवेदी ने कहा है कि शुआट्स कुलपति आरबी लाल की टीम के खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत और प्रशासनिक कार्यवाही कराई जा रही है। जिसके कारण उक्त टीम द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से झूठी एफआईआर लिखवा कर मुझे सामाजिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डॉ. द्विवेदी का कहना है कि शुआट्स के कुलपति आरबी लाल और उनकी टीम द्वारा उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उक्त घटना की किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से आरबी लाल द्वारा चंगाई यीशु दरबार खोलकर धर्मांतरण कराया जाना, शुआट्स में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्जनों शिकायतें की गई। जिसमें सरकारी ग्रांट का दुरुपयोग, एक्सिस बैंक घोटाला, सरकारी जमीन को अपने नाम करवाना, प्रतीक्षा जैकब का बलात्कार कर हत्या करना, विलियम्स हालैंड हाल छात्रावास में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत एसआईटी द्वारा जांच की मांग करना आदि है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पूर्व उन पर प्राणघातक हमला भी कराया गया। जिसकी एफआईआर जार्जटाउन थाने में दर्ज है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई पेंच हैं। यदि सही जांच हो जाय और पूंछताछ हो जाय तो मामले का पदार्फाश हो जायेगा।

जेवर साफ करने के बहाने उड़ा दिए ढ़ाई लाख का आभूषण

घूरपुर। जेवर साफ करने के बहाने एक ईंट कारोबारी के घर पहुंचे पल्सर सवार उचक्कों ने कारोबारी के पत्नी को चकमा दे ढाई लाख कीमत के सोने के जेवर पार कर भाग निकले ।महिला को पता चला तो शोर मचाया तब तक उचक्के नजरों से ओझल हो चुके थे ।सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की ।

घूरपुर बाजार निवासी गया प्रसाद केसरवानी ईंट कारोबारी हैं। उनके घर में शुक्रवार की दोपहर उनकी पत्नी रीना केसरवानी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ थी । इसी बीच दो युवक पल्सर से पहुंचे और दरवाजा खटखटा कर घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद दोनों ने अपने को जेवर साफ करने वाला बताया। दोनो उचक्कों ने रीना केसरवानी को अपने झांसे में ले लिया। रीना घर के अंदर गई और अपना चार सोने के कड़े और एक सोने की वजनी चैन लेकर उचक्कों के पास पहुंची। उचक्कों ने जेवर को उलट पलट कर देखने के बाद उन्हें साफ करने के लिए गरम पानी की मांग की तो रीना अपने दो छोटे बच्चों को छोड़ रसोई में जाकर पानी गरम करने लगी। इसी बीच उचक्कों ने जेवर समेटा और पल्सर पर सवार होकर शहर की ओर भाग निकले। पानी लेकर रीना वापस आई तो गहने साफ करने वालों को देख दंग रह गई। रीना ने शोर मचाया तो आस पास के लोग जुट गए और बाइक से युवकों का पीछा किया लेकिन उचक्के भागने में सफल रहे। सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की। भरे बाजार दिन दहाड़े हुई इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कम्प मचा हुआ है।

एडीओ पंचायत सैदाबाद का रिश्वत लेते वीडियो वायरल

हंड़िया। हंड़िया तहसील क्षेत्र के विकास खण्ड सैदाबाद में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी मणिकांत का रिश्वत लेते हुए वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसको लेकर इस वीडियो की सत्यता की जांच की गई। तो पता चला कि यह जो पैसे पंचायत द्वारा लिए गए हैं। यह ग्राम प्रधानों से लिए गए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो सभी प्रधानों से 3 परसेंट जिले के अधिकारियों के नाम से सहायक विकास अधिकारी सैदाबाद मणिकांत उपाध्याय द्वारा लिया जाता है। वही सहायक विकास अधिकारी मणिकांत द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस पैसे में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। केवल हमने लिया है। यह उच्च अधिकारियों तक जाएगा।अब हम पैसे नहीं लेंगे अब सीधा प्रधानों से कह देंगे कि जाकर उच्च अधिकारियों से मिलकर वहां पैसे दे। दूसरे वीडियो में सहायक विकास अधिकारी मणिकांत ने अंजना के वर्तमान प्रधान से कहा कि तुम्हारा 2,10000 का स्टीमेट है।उसमें से तुम्हारा 3 परसेंट की दर से.7000 रुपये बनता है। जो तुम्हें देना पड़ेगा।जबकि ग्राम प्रधान द्वारा 4000 दिया गया लेकिन एडीओ पंचायत ने लेने से इंकार कर दिया। कहा कि 7000 की पूरी रकम मुझे चाहिए नहीं तो मैं नहीं लूंगा। क्योंकि यह ऊपर तक अधिकारियों के पास जाएगा जो की वीडियो में साफ तौर से देखा और सुना जा रहा है।

सेवा व समर्पण का पर्याय हैं नरेन्द्र मोदी: डॉ शैलेश पाण्डेय

प्रयागराज। आज पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा और समर्पण का पर्याय बन चुके हैं। उनका सेवा भाव कोरोना काल में पूरे विश्व ने देखा और उसकी प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पूरी तरह सुरक्षित और प्रगतिशील है। उनके नेतृत्व में भारत का निरंतर विकास हो रहा है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र शिक्षक प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ. शैलेश कुमार पाण्डेय ने गुरूवार को प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर अन्न वितरण कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा कि आज विश्व की महाशक्तियां हमारे देश की ओर आशा भारी नजरों से देख रही हैं। सैन्य क्षेत्र से लेकर, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है ।

घरेलू कलह से क्षुब्ध दुकानदार ने गोली मारकर की आत्महत्या

प्रयागराज। करेली थाना क्षेत्र के नारायनपुर मोहल्ले में शुक्रवार दोपहर युवा दुकानदार ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह घरेलू कलह बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

करेली के करेलाबाग नारायनपुर मोहल्ला निवासी अमर सिंह साहू (30) पुत्र श्याम सुन्दर साहू दो बहनों के बीच में अकेला भाई था। एक बेटी और पत्नी नेहा साहू एवं पूरे परिवार के भरण-पोषण के लिए घर के आगे हिस्से में किराने की दुकान खोला था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर घर के अन्दर तमंचे से अपने मत्थे पर गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य एवं पड़ोसी पहुंचे तो वह लहूलुहान पड़ा था। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी और उपचार के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया तथा शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। उधर घटना की खबर मिलते ही क्षेत्राधिकारी प्रथम और अपर पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू कलह से जुड़ा लग रहा है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक घरेलू कलह की वजह से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी जांच जारी है।

आरोग्य केंद्र पर निःशुल्क करवाएं मधुमेह और बीपी की जांच

शंकरगढ़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ के अंतर्गत आने वाले आरोग्य केंद्र कल्याणपुर द्वारा ग्रामवासियों को गैर संचारी रोगों से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले ग्रामवासियों को ब्लड प्रेशर एवं सुगर जैसी बीमारियों हेतु निःशुल्क जांच सुविधाएं एवं परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इस आरोग्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया गया है। यहां कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अभिषेक जायसवाल द्वारा बताया गया कि उक्त आरोग्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले समस्त 30 वर्ष से अधिक उम्र के ग्रामवासियों को वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से गैर संचारी रोग की जांच हेतु सलाह दी जा रही है। इस दौरान ब्लड प्रेशर एवं सुगर से पीड़ित पाए गए लोगों को वांछित उपचार भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया की इस हेतु आरोग्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली समस्त आशाओं द्वारा गांव के अंतर्गत आने वाले समस्त परिवारों हेतु एक नियत प्रारूप पर फॉर्म भी भरवाया जा रहा है, जिसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का बीमारियों के नजदीक होने का आकलन करते हुए उन्हें आशाओं के माध्यम से आरोग्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में ऐसे व्यक्ति जो दूर दराज के क्षेत्रों से है और किसी कारणवश आरोग्य केंद्र आने में असमर्थ हैं, उनके लिए समय-समय समय पर गांव के अंदर जाकर आउटरीच सेशन एवं एएनएम द्वारा टीकाकरण सत्र के दौरान भी जांच सुविधा प्रदान की जा रही है। सप्ताह में नियत दिवस पर लोगों को केंद्र पर ही छोटी -मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रारंभिक उपचार हेतु निशुल्क दवाइयां व स्वास्थ्य सलाह भी प्रदान की जा रही है।

लोगों की जांच करते चिकित्सक

एमपी की सीमा पर लगा हेल्थ कैंप

शंकरगढ़। मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास स्थित बेवरी गांव में भी गैर संचारी रोगों की जाँच हेतु हेल्थ कैंप का आयोजन आशा अनंता देवी एवं कोटेदार मेवालाल जी के सहयोग से किया गया जिसमे लगभग 30 व्यक्तियों की जाँच की गयी तथा आवश्यक उपचार हेतु आरोग्य केंद्र की सुविधा लेने की सलाह देते ही कोरोना महामारी से बचने के तरीकों के बारे में भी आमजनो को जागरूक किया गया।

गलत वेतन निर्धारण से अधिक भुगतान की वसूली पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य बंदी रक्षकों के वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुशील कुमार दीक्षित सहित आठ याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर पक्ष रख रहे अधिवक्ता का कहना था कि याची के वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद पता चला कि अधिक वेतन भुगतान किया जा रहा था। इसमें याची की कोई भूमिका नहीं है। विभाग की लापरवाही से ऐसा किया गया है। याचियों को सुनवाई का मौका दिये बगैर उनसे भुगतान किए गए अधिक वेतन की एक पक्षीय वसूली कार्यवाई की जा रही है।

हाईकोर्ट समाचार

एनजीओ को गांव सभा की जमीन देने का आदेश रद्द करने को चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1985 में गांव सभा की जमीन एनजीओ को पट्टे पर देने के आदेश को निरस्त करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने डाक्टर बीआर अंबेडकर मल्टीपर्पज रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसे जिलाधिकारी ने 20 जुलाई 85 को जमीन दी थी। जिलाधिकारी मैनपुरी ने 9 सितम्बर 20 के आदेश से आवंटन निरस्त कर गांव सभा को वापस कर दी। इसी आशय का आदेश राज्य सरकार ने भी दिया है। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी व ए सी एस सी शशांक शेखर सिंह का कहना था कि उप्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून की धारा 117(6) के अंतर्गत जिलाधिकारी को गांव सभा की जमीन किसी एनजीओ को देने का अधिकार नहीं है। 20 जुलाई 85 का आदेश शुरू से ही विधि विरूद्ध है। ऐसे में उसे निरस्त करने का आदेश सही है। उन्होंने कोर्ट से याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा।

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण को निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड मछलीशहर जौनपुर को सथरिया प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ विद्युत चोरी की नोटिस के खिलाफ याची की आपत्ति एक माह में तय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने फैक्ट्री मालिक पवन कुमार केशरवानी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरूण मिश्र व महावीर यादव तथा विजली विभाग के अधिवक्ता महबूब अहमद ने पक्ष रखा। बिजली विभाग ने याची के खिलाफ 22 लाख 54 हजार 998 रुपए की विद्युत चोरी की नोटिस जारी की है। चोरी के आरोप को नकारते हुए याची ने आपत्ति की है। जिस पर निर्णय न लेकर कार्यवाही की धमकी देने पर यह याचिका दाखिल की गयी है। बिजली विभाग के अधिवक्ता का कहना था कि आपत्ति एक माह मे तय कर दिया जायेगा। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

फार्म की हार्ड कापी लेकर अभ्यर्थी को पीसीएस मुख्य परीक्षा में बैठने देने का आयोग को निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 सितम्बर से होने वाली उप्र लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा फार्म की याची अभ्यर्थी से हार्ड कापी स्वीकार कर परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है। कोविड 19 के चलते देशव्यापी लाकडाउन व कन्टेनमेन्ट जोन में फंसे होने के कारण आनलाइन भरे गये फार्म की हार्ड कापी निर्धारित अवधि के बाद जमा करने गया तो आयोग ने स्वीकार नहीं किया। जिस पर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थिति के कारण फार्म जमा करने में देरी हुई है। जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आयोग दाखिल दस्तावेजों का सत्यापन कर मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। कोर्ट ने आयोग से याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब भी मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता ने प्रयागराज के सार्थक रहेजा की याचिका पर दिया है । मालूम हो कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल याची ने मुख्य परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन भरा है। जिसे डाउनलोड कर आयोग में 26 मार्च तक जमा करना था। यदि डाक से भेजा जाता तो 26 मार्च तक आयोग को मिल जाता। याची का कहना है कि वह दिल्ली में था। कोरोना के चलते देशव्यापी लाकडाउन लागू कर दिया गया। इसके बाद वह कन्टेनमेन्ट जोन में फंस गया। सारे शैक्षिक दस्तावेज प्रयागराज में थे। वह डाक से फार्म भेजने की स्थिति में नहीं था। लाकडाउन खुलने के बाद प्रयागराज आया और 15 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन में रहा। 16 जून को फार्म जमा करने आयोग पहुंचा तो जमा करने से इंकार कर दिया गया। उसी समय डाक से भेजा। किन्तु कोई निर्णय नहीं लेने पर कोर्ट की शरण ली है। आयोग के अधिवक्ता का कहना है कि याची ने आनलाइन फार्म 27 फरवरी को ही डाउनलोड कर लिया था। उसे अंतिम तिथि तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। आयोग ने 15 मई तक फार्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी थी। फिर भी याची समय से फार्म जमा नहीं कर सका।

संग्रह अमीन की बहाली के खिलाफ सरकार की विशेष अपील खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संग्रह अमीन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द करके उसकी बहाली और 75 प्रतिशत बकाया भुगतान करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। अपील में एकल न्यायपीठ के 15 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ ने सुनवाई की। राज्य सरकार का कहना था कि विपक्षी अमीन को पिछले बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी अपील तथ्यों पर निस्तारित नहीं की गई है। कोर्ट का कहना था कि जिलाधिकारी ने अमीन बृजलाल के खिलाफ की गई जांच तीन बार अस्वीकार कर सही जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने सही तरीके से जांच नहीं की और तीसरी बार की गई जांच में अमीन को अपना पक्ष रखने का सही तरीके से मौका नहीं दिया गया। और दूसरी जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर तीसरी रिपोर्ट दे दी गई। इस आदेश के खिलाफ कमिश्नर के यहां उसकी अपील 12 वर्षों तक लंबित रही। इस सब में विपक्षी अमीन का कोई दोष नहीं है। इस आधार पर एकल न्यायपीठ ने 75 प्रतिशत बकाया के साथ वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान का आदेश याची अमीन के पक्ष में दिया था। कोर्ट ने कहा कि एकल जज के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही करार दिया है।

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी व परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र प्रसाद तिवारी व परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारी की है और पूछा है कि क्यों न उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित किया जाय। कोर्ट ने 23 नवंबर तक दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता ने भदोही के अनुदेशक आशुतोष शुक्ल की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अनुदेशको को मानदेय के रूप में 8 हजार रुपए दिये जा रहे हैं। जबकि केन्द्र सरकार ने मानदेय बढ़ा कर 17 हजार प्रतिमाह कर दिया है। राज्य सरकार इस आदेश का पालन नहीं कर रही है। जिस पर याचिका दाखिल की गयी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के आदेश का पालन कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने छह हफ्ते में पालन का निर्देश दिया। फिर भी कोर्ट के आदेश का अवहेलना की गयी तो दुबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

प्रयागराज हलचल

संक्षेप समाचार

स्थगन आदेश के बावजूद हो रहा पंचायत भवन का निर्माण

करछना। गांवों में नवनिर्मित पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्वच्छ शौचालयों के बनाये जाने की योजना को लेकर जहां प्रधानो द्धारा इसकी कवायत की जा रही है वही जमीनी विवाद और कई अड़चनों के चलते आपसी विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। इसके चलते कुछ गांवों में पंचायतों भवनों और शौचालयों का निर्माण अधर में पड़ा हुआ है।इन्हे बनाये जाने के लिए गांव में भूमि चयन को लेकर किसानों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही है तो वही कई जगह नवैयत बदल जाने से मानक के अनुसार जमीन नही मिल पा रही है।ग्रामीणों का आरोप है कि कई गांवों में प्रधान द्धारा अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन निर्माण कराया जा रहा है।क्षेत्र के अंतहिया गांव में ब्रहमा प्रसाद को कोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बावजूद राजस्वकर्मियों की मिलीभगत से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है।आरोप है कि ग्राम प्रधान के परिजनों द्धारा कास्तकार के खेत में राजस्व कर्मियो की सांठ.गांठ और राजनैतिक खुन्नस को लेकर जबरन निर्माण कराया जा रहा है।

ड्राइवर ने कुल्हाड़ी से बेटे व पत्नी को मौत के घाट उतारा

बड़े बेटे एवं खुद को घायल कर आरोपी पति फरार

प्रयागराज। कोरांव थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव में गुरुवार की रात छोटे बेटे की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी और पत्नी एवं बड़े बेटे को घायल कर आरोपी पति खुद को घायल करने के बाद फरार हो गया। हालांकि बाद में पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है।

कोरांव के बड़ोखर गांव निवासी पुष्पराज सिंह खेती एवं प्राइवेट वाहन चलाकर पत्नी सुनीता (32)और दो बेटे राज सिंह (7) एवं रत्न सिंह (10) का भरण-पोषण करता है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात घरेलू विवाद की वजह से पुष्पराज सिंह ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाया और पत्नी एवं बच्चों पर प्राणघातक हमला कर दिया। पत्नी और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो पुष्पराज सिंह ने भागते हुए खुद को भी कुल्हाड़ी से वार करके मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर कोरांव थाना प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और हमले में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सकों ने सात वर्षीय राज सिंह को मृत घोषित कर दिया और उसकी मां सुनीता एवं बड़े बेटे को तत्काल स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय के लिए भेज दिया। जहां उपचार के दौरान सुनीता की भी कुछ देर बाद मौत हो गई।

घटना के बाद जुटी ग्रामीणों की भीड़

सनसनीखेज वारदात की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार चक्रेश मिश्रा समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके से फरार आरोपी पति की तलाश जारी है। उक्त जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक यमुनापार चक्रेश मिश्रा ने बताया कि ट्रक चालक ने अपनी व एक बेटे की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी है और बड़े बेटे को घायल करने के बाद फरार हो गया। इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़े फैक्ट्रियों को कराया जाए चालू : संजय श्रीवास्तव

नैनी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महानगर के महामंत्री संजय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बैठक काटन मील तिराहे के समीप संपन्न किया गया। कार्यकताओं ने औघोगिक नगरी नैनी क्षेत्र के बंद पड़ी इकाइयों को पुनः चालू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील किया गया। महामंत्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और हजारों की संख्या में गरीब मजदूर श्रमिक रहते हैं। इन कंपनियों को चालू होने से बहुत से गरीबों व व्यापारियों का भला होगा और अनेक उद्योग धंधे बंद पड़ी हुई हैं। पुनः चालू कराया जाए जिससे औद्योगिक क्षेत्र जो नाम पड़ा है उसको फलीभूत किया जा सके। इस दौरान जिला अध्यक्ष लल्लन सिंह पटेल, मृत्युंजय कुमार, नीरज शर्मा, सुनील कुमार विश्वकर्मा, नित्यानंद मिश्रा, प्रदीप गौड़, रजनीश उपाध्याय, जनार्दन शुक्ला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रयागराज मंडल का बरगढ़ स्टेशन हुआ आधुनिक ड्युएल वीडीयू से लैस

प्रयागराज। सिग्नल और दूरसंचार विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य को पूरा करते हुए 15 सितम्बर को प्रयागराज-मानिकपुर खंड के बरगढ़ स्टेशन पर ड्युएल वी.डी.यू के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के हॉट स्टैंडबाई की कमीशनिंग की गई। इसके लागू हो जाने से वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है। अब दो में से किसी भी एक सिस्टम में खराबी आने पर सिग्नल प्रणाली बिना किसी रुकावट के लगातार कार्य करती रहेगी। क्योंकि दूसरी वैकल्पिक प्रणाली तत्काल काम करना चालू कर देगी।

जबकि पहले ऐसा होने पर सिगनलिंग प्रक्रिया चालू होने में तीन मिनट का समय लगता था तथा स्टेशन के सभी सिग्नल लाल होने से अप एवं डाउन की गाड़ियां रूक जाती थीं। सिग्नल विभाग द्वारा किये गए इस कार्य से इस सेक्शन की ट्रेनों के समयपालन में सुधार तो होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की विफलता में भी कमी आएगी। जनसम्पर्क अधिकारी केशव त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज मंडल से अलीगढ़ के नजदीक हरदुआगंज में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा सामान की ढुलाई के लिए कंपनी की फैक्टरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग लगातार की जा रही थी। हालांकि, हरदुआगंज जैसे 117 रुट के पैनल इंटरलॉकिंग वाले स्टेशन से अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को जोड़ने वाली साइडिंग की इंटरलॉकिंग सिग्नल विभाग के लिए एक अत्यन्त जटिल कार्य था। सिगनल विभाग ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए लगातार कठिन परिश्रम करके हरदुआगंज स्टेशन पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के लिए बनाई गई रेलवे साइडिंग को स्टेशन के पैनल इंटरलॉकिंग के साथ 14 सितंबर को इंटरलॉक किया। इस कार्य में कंपनी से आने-जाने वाली मालगाड़ियों को हरदुआगंज स्टेशन की विभिन्न लाइनों से संचालित करने के लिए 7 नई प्वाइंट मशीनें लगाई गई हैं। इन मालगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए चार पारंपरिक ट्रैक सर्किट के साथ साथ तीन एक्सल काउंटर ट्रैक सर्किट डुअल डिटेक्शन सहित लगाए गए। ट्रेनों के नई रेल लाइनों से सुरक्षित आगमन प्रस्थान के लिए 4 नए सिगनलों के साथ 4 डिपेंडेंट तथा 4 इंडिपेंडेंट शंट सिगनल लगाए गए हैं। सिगनलिंग डाटा के ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं एनलाइसिस के लिए 512 डिजिटल इनपुट का डाटा लॉगर लगाया गया है।

कांग्रेसियों ने ओवरलोड ट्रकों व अवैध वसूली को लेकर दिया ज्ञापन

करछना। युवा काग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र तिवारी के नेतृत्व मे काग्रेस कार्यकर्ताओ का एक प्रतिनिधि मडल ओवरलोड ट्रको के संचालन पर मुगारी टोल प्लाजा अवैध ढग ओवरलोडिग गाडियो से वसूली को लेकर तहसीलदार करछना को ज्ञापन सौपा।काग्रेसियो ने ज्ञआपन मे आरोपित किया है कि पिछले कुछ माह से टोलबूथ पर अवैध वसूली को लेकर मारपीट की घटनाए ज्यादा हुई है और अनवरत जारी भी हैएजिसे जल्द नही रोका गया तो कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन को बाध्य होगे। इस मौके पर अमजद अंसारी, प्रांजल केसरवानी मोनू यादव, सत्यम, प्रवीण तिवारी, अमन आदि रहे।

बकाया भुगतान न होने पर होगा मेला टेण्डर का बहिष्कार : अनिल यादव

प्रयागराज। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ठेकेदार संघ के तत्वावधान में सिविल लाइंस स्थित होटल में शुक्रवार को संघ के पदाधिकारियों की बैठक माघ मेले के बकाया 50 करोड़ रुपये के भुगतान की मेला प्रशासन और सरकार से मांग को लेकर हुई। जिसमें विगत 15 वर्षों से ठेकेदारों के भुगतान तथा श्रमिकों के धरने से प्राप्त ठेकेदारों की परेशानी पर चर्चा हुई।

प्रशासन द्वारा माघ मेला 2019-20 के लोक निर्माण विभाग, बिजली और जल निगम के 20 करोड़ बकाया के शीघ्र भुगतान की मांग की गयी। संघ अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि कोविड-19 के वजह से जो स्थिति हुई है उस पर प्रशासन तथा विभागों के अधिकारी भुगतान पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जिससे वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि ठेकेदारों के घरों पर श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। जबकि ठेकेदारों को खुद खाने का नहीं है तो श्रमिकों को क्या दें। कई वर्षों से ठेकेदार इस आशा से कार्य करते चले आ रहे हैं कि अगले वर्ष भुगतान हो जाएगा, मगर वर्तमान में स्थिति यह है कि कोई भी ठेकेदार अब कार्य करने की स्थिति में नहीं है। बैठक में कहा गया कि जिलाधिकारी ने 30 जुलाई 2020 को अवशेष धनराशि 44,52,19,675 रू के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास, उप्र शासन लखनऊ को पत्र लिखा, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। कहा गया कि अब 24 सितम्बर को बैठक होगी उसके बाद आगामी माघ मेला के बारे में फैसला लिया जायेगा। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि हम सभी ठेकेदार उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द भुगतान करने का कष्ट करें जिससे ठेकेदार व सड़कों की स्थिति सही हो सके। इस अवसर पर अध्यक्ष अनिल यादव जल निगम, महामंत्री आशीष कुमार द्विवेदी विद्युत विभाग, उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग से राकेश वैश्य व राजा मुन्ना, कोषाध्यक्ष मनीष मेहरा पीडब्ल्यूडी मंत्री लकी श्रीवास्तव एवं अशफाक अहमद जल निगम आदि उपस्थित रहे।

असंगठित कामगारों को पेंशन योजना लॉच : उपकर आयुक्त

प्रयागराज। असंगठित कामगारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने पेंशन योजना लॉन्च किया है। जिसका लाभ 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के श्रमिकों को मिलेगा।

उक्त विचार श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के कल्याण एवं उपकर आयुक्त चन्द्रदेव ने शुक्रवार को दांदूपुर स्थित समदरिया स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन में आयोजित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना-परिचर्चा में बतौर मुख्य वक्ता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना अंशदान पद्वति पर आधारित है जो मासिक किश्त के रूप में लाभार्थी के खाते से कटेगी और उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा उस खाते में प्रेषित करके उसे दोगुना करेगी। इस प्रकार 60 वर्ष बाद पंजीकृत श्रमिक लाभार्थी को 3000 रुपये मासिक पेंशन आजीवन मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में कामगारों की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। असंगठित श्रमिकों में प्रायः सामाजिक सुरक्षा का अभाव खटकता है। आवश्यकता है कि इन्हें शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की अनुभूति हो सके। केंद्र सरकार इसके लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष के श्रमिकों को मात्र 55 रुपये मासिक अंशदान जमा करना होगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को दे रखी है।

जानकारी देते कल्याण एवं उपकर आयुक्त चंद्र देव

अध्यक्षता करते हुए रमाकांत त्रिपाठी ने कहा कि प्रभावी श्रम कानून न लागू होने के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। उनका रोजगार और वेतन दोनों सुनिश्चित नहीं है। ऐसे में भविष्य निधि की परिकल्पना करना कठिन है। अतिथियों का स्वागत संस्थान के निदेशक डॉ. मणि शंकर द्विवेदी ने एवं संचालन रण बहादुर सिंह ने तथा आभार ज्ञापन कोऑर्डिनेटर विनीत पांडे ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रभाकांत तिवारी, रुचिता केसरवानी, नीतू सिंह, सुमन, सरला गौर, उषा प्रजापति, जैनुल अब्बास, लियाकत हुसैन, बदर मुर्तजा, सेरात मेंहदी आदि लोग मौजूद रहे।

प्रयागराज टीचर्स गेम्स एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी गठित

प्रयागराज। प्रदेश में बच्चों व शिक्षकों के खेल एवं स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के खेल में रुचि रखने वाले सरकारी-गैर सरकारी तथा खेल व्यायाम शिक्षकों व अनुदेशकों द्वारा प्रदेश में ह्लउत्तर प्रदेश टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशनह्व का गठन किया गया। जिसमें प्रदेश सचिव प्रयागराज के आशुतोष सिंह को बनाया गया।

यह जानकारी प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने देते हुए बताया कि प्रदेश संघ के निदेर्शानुसार प्रयागराज टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसियेशन की इकाई के गठन के लिए प्रदेश पर्यवेक्षक की देख-रेख में प्रयागराज जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से जिला व्यायाम शिक्षिका लक्ष्मी सोनकर को जिलाध्यक्ष के पद पर तथा ब्लॉक कौंधियारा के अनिमेष श्रीवास्तव को जिला सचिव व चाका ब्लॉक के सुनील कुमार को कोषाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुना गया। साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर धनूपुर ब्लॉक के यशवंत सिंह तथा उपाध्यक्ष के पद पर सुनील त्रिपाठी होलागढ़, जितेंद्र राम कोरांव व श्रद्धा श्रीवास्तव सैदाबाद को चुना गया। वहीं संयुक्त सचिव के पद पर सुधीश कुमार जसरा, रीता शर्मा सोरांव व दिनेश प्रताप सिंह प्रतापपुर को चुना गया तथा लालजी धुरिया, अमर बहादुर पटेल व श्वेता सोनकर को जिला खो-खो प्रभारी की जिम्मेदारी दी गयी। ओम प्रकाश कुशवाहा व लाल साहब को जिला कबड्डी प्रभारी बनाया गया।

नवनियुक्त पदाधिकारीगण

अजय यादव, चंद्रशेखर भारतीय (उरुवा), रामबहादुर यादव, अवधेश शुक्ला, कंचन यादव, शशि सिंह, शशिकांत तिवारी व दिवाकर सिंह को जिला एथलेटिक्स प्रभारी तथा अभिषेक सिंह को जिम्नास्टिक, प्रियब्रत कुमार को जूडो, सुनील शुक्ला को वालीबाल, अनिकेत जायसवाल को फुटबाल, अभिषेक जायसवाल, स्नेहलता व प्रदीप त्रिपाठी को योगा, राजेश सिंह को कराटे, विजय राज व रोहित राजपूत को हैंडबाल, राहुल कनौजिया को टेबल टेनिस, दयानंद को कुश्ती, संकेत यादव, संदीप कुमार, मो.नवी, सुजाता दूबे व आरती को क्रिकेट, रक्षा जायसवाल को ताइक्वांडो, शैलेंद्र कुशवाहा को हाकी, राजेन्द्र यादव को बास्केटबाल, अवधेश कुमार को बैडमिंटन का जिला प्रभारी बनाया गया। प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने बताया कि प्रयागराज से तीन लोगों को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। जिसमें प्रयागराज से वॉलीबाल के राष्ट्रीय खिलाड़ी व अंतरराष्ट्रीय वॉलीबाल कोच मुकेश शुक्ला को वॉलीबाल का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रयागराज के अभिषेक सिंह (शंकरगढ़) को जिम्नास्टिक का प्रदेश प्रभारी तथा प्रीती तिवारी (कोरांव) को महिला क्रिकेट का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। टीचर्स गेम्स एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रयागराज जिला कार्यकारिणी को प्रदेश संघ के पदाधिकारियों ने अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी है।

एमबीए एमसीए में प्रवेश तिथि तीस सितम्बर तक बढ़ी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के एमबीए और एमसीए में प्रवेश तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों को अब प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय ने दो दिन पूर्व ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देने का निर्णय ले लिया है। यह जानकारी मुक्त विवि के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. प्रभात चंद्र मिश्र ने देते हुए बताया कि प्रवेश परीक्षा न होने से प्रवेश लेने वाले छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि विस्तारित कर दिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के 19 अगस्त 2020 के सर्कुलर तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा एवं विज्ञान विद्या शाखा के संयुक्त स्कूल बोर्ड के प्रस्ताव के दृष्टिगत कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने सत्र 2020-21 की एमबीए तथा एमसीए प्रवेश परीक्षा को न कराए जाने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रवेश प्रभारी डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव ने बताया अब विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन न कर निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक शिक्षार्थी पूर्व की भांति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराते हुए प्रवेश हेतु आवेदन करें।

मऊआइमा में ग्राम विकास अधिकारी सफाई कर्मचारी सहित दो पाजिटिव

मऊआइमा। कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को जांच के बाद मऊआइमा विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी एंव विकास कार्यालयके सफाई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों को होम क्वालंटाइन कर दिया गया है।

मऊआइमा में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है ।शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जांच की गई तो विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी 27 वर्ष तथा यही का सफाई कर्मचारी 41 वर्ष कोरोना पाजिटिव पाए गए। दोनों को विकास कार्यलय के सरकारी आवास में ही क्वालंटाइन कर दिया गया है । इसके पूर्व एडीओ पंचायत तथा मऊआइमा कस्बा के चुनौंटा कुआं स्थित बैंक के मैनेजर और कैशियर तथा गंजियाबाजार की दो महिलाएं कोरोना पाजिटिव पाए गए थे । सभी को होम क्वालंटाइन कर दिया गया है ।कोरोना का कहर कम होने के बजाय रोज बढता ही जा रहा है ।जिससे लोग खौफजदा हैं । हालांकि अब कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही कर रहा है । जिससे कोरोना संक्रमण बढ रहा है। अब सभी को राम भरोसे छोड दिया गया है ।

विकास प्राधिकरण की 128 वीं बोर्ड की बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

प्रयागराज। शुक्रवार को विकास प्राधिकरण के सभागार में 128 वीं बोर्ड की बैठक में मंडलआयुक्त प्रयागराज मंडल अध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण आर रमेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी समन योजना 2020 को प्रयागराज विकास प्राधिकरण में 21 जुलाई से लागू कर दिया गया है। कुंभ मेला 2019 के दौरान शासन एवं प्राधिकरण की अवस्थापना से प्राप्त धनराशि से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कराए गए सड़कों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण के कार्यों को रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग, नगर निगम प्रयागराज को हस्तांतरित किया जाना है। उक्त सड़कों के हस्तांतरण से पूर्व यथा आवश्यक पैच वर्क का कार्य प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि से कराया जाना है। चौराहों पर निर्मित रोटरियों, स्कल्पचर्स/ म्यूरल्स का रखरखाव प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि से कराया जाना है स्कल्पचर्स, न्यूरल्स पर पर लगी लाइटों को विद्युत बीजक का भुगतान नगर निगम प्रयागराज द्वारा अपने स्ट्रीट लाइटों के विद्युत बीजक के साथ किया जाएगा मौसम विहार योजना कालिंदीपुरम में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैट के वित्तीय वर्ष 2019 -20 बैच के विक्रय मूल्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु फ्रीज करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कसारी मसारी योजना अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखंड को व्यवसायिक में परिवर्तन करने से पूर्व जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए, वहीं नैनी में प्रस्तावित नवीन टाउनशिप के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मुख्य रूप से अंकित कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण, जिला अधिकारी कौशांबी अमित कुमार सिंह, नगर आयुक्त रवि रंजन गंगाराम गुप्ता, अपर जिलाधिकारी नजूल राजेंद्र मिश्र,ा रणजीत सिंह, कमलेश कुमार, शासन द्वारा नाम सदस्यों के साथ-साथ अन्य सदस्य के अतिरिक्त दयानंद प्रसाद सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण उपस्थित रहे।

बैठक की अध्यक्षता करते मण्डलायुक्त

अखण्ड भारत सन्देश

प्रयागराज, शनिवार, 19 सितम्बर, 2020

क्रियायोग सन्देश

आज आवश्यकता है कि हम राजनीति को ठीक तरह से समझें

राजनीति में छिपी हुई सच्ची भावना व सच्चे विचार को अनुभव करने पर राष्ट्र में स्थित मनुष्य, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, तलाब, झील, नदी, पहाड़ आदि को पर्याप्त संरक्षण आसानी से प्रदान करते हुए आवश्यकता के अनुकूल सभी प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराया जा सकता है। 'राज' व 'नीति' के संयोग से ''राजनीति'' बना है।

''राज'' 'राजयोग'' से प्राप्त हुआ है और नीति राजयोग में व्यवस्थित नियम को संबोधित करता है। वशिष्टमुनि, गुरुविश्वामित्र, भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, महर्षि पतंजलि, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, संतकबीर, नानकदेव, योगिराज लाहिड़ी महाशय ने राजयोग की शिक्षा दिया है। राजयोग शब्द स्पष्ट करता है कि योग की अवस्था में मनुष्य की स्थिति राजा के रूप में होती है। सामान्य लोग अपने जीवन काल में जिस सुख दुःख, लाभ-हानि, पाप-पुण्य, यश-अपयश की अनुभूति में होते है, राजा इन सभी द्वन्दात्मक अनुभूतियों से परे की अवस्था में रहता है। राजा प्रति पल सच्चे ज्ञान, चिर शांति, अमरता, सर्वव्यापकता की अनुभूति में रहता है। सामान्य लोग राजा के द्वारा किये गये क्रियाकलाप को समझ नहीं पाते हैं और जब समझने का प्रयास करते हैं तो गलत निष्कर्श पर पहुॅचते हैं। सामान्य धारणा है राजा राम व श्रीकृष्ण आदि के जीवन में बहुत कष्ट हुआ। वे लोग कभी भी सुख व चैन से जीवन नही बिता सके। वास्तविकता इसके विपरीत है। भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण प्रतिपल सर्वज्ञता व सर्वव्यापकता की अनुभूति में रहते थे। वे जीवन में कभी भी सुख--दुःख का अनुभवन ही किये। वे हमेशा परमानन्द की अनुभूति में रहते थे।

योग की अवस्था में जब मनुष्य अपनी उपस्थिति राजा के रूप में अनुभव करता है तब उसे राष्ट्र के विविध रचनाओं को संरक्षण देने, उनका मार्ग दर्शन करने और उन्हें पर्याप्त सुख-सुविधा पहुँचाने में सक्षम होता है। राजा के संरक्षण में समस्त प्रजा भयरहित व अभावरहित स्थिति में होती है। आज आवश्यकता है कि राजा के बिगड़े हुए स्वरूप को सभी लोग समझें। जैसे-जैसे क्रियायोग ध्यान का दीप घर-घर में जलेगा वैसे-वैसे मनुष्य वास्तविक राजा का चयन कर वैभवशाली राष्ट्र बनाने में सफल होगा।

सच्चे राजा के व्यक्तिगत रहन-सहन के लिए सुविधाएँ व धन सामान्य जनता की आवश्यकताओं से बहुत कम होता है और राजा की नीति निर्धारण हेतु जो लोग विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका में होते हैं उनका भी व्यक्तिगत दैनिक खर्च सामान्य जनता के लिए प्रयुक्त धन से कम होता है। जो लोग अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं, वे शारीरिक बीमारियों व सभी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्त होते हैं। आज आवश्यकता है राजा के रूप में सही व्यक्तियों का चुनाव हो जिससे राष्ट्र के सभी मनुष्य, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, तलाब, झील, नदी, पहाड़ व समुद्र का ठीक तरह से संरक्षण व व्यवस्था हो।

आज आवश्यकता है कि राष्ट्र के सभी लोगों में समझने की सामर्थ्य बढ़े। वे सच्चे राजा का चयन कर सकें। लोगों में समझ बढ़ाने की शिक्षा प्रणाली का अभाव है। ''पढ़ कर याद करने, लिखने और कहने की अभिव्यक्ति में जो खरा उतरता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। विचार करके देखें तो स्पष्ट है कि कम्प्यूटर, सेलफोनए एमपीथ्री प्लेयर व सभी प्रकार के टेपरिकार्ड आदि किसी भी शब्द या वाक्य को सुनते ही याद कर लेते हैं और बिना किसी गल्ती के उसकी अभिव्यक्ति बोलकर व लिखकर प्रस्तुत करने में पूर्णतया सफल हैं। हम इन मशीनों को बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं।

''पढ़कर, याद करके लिखने और कहने की अभिव्यक्ति में जो खरा उतरता है उसे बुद्धिमान कहने की परम्परा गलत है।'' बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो अनुसंधान में रत है और अपने वस भी मनुष्यों के अंदर तथा ब्रह्माण्ड की सभी रचनाओं में निहित अनन्तज्ञान व शक्ति की उत्तरोत्तर खोज करने में नित्य नये आनन्द को प्राप्त होता है।

True Concept of Politics (Rajniti)

In the present time, there is an urgent need to understand the true concept concealed within the word Rajniti (politics). The time and moment human beings will experience true idea and true concept hidden within the word politics (Rajniti), then there will be real service and protection for all human beings, animals, plants, ponds, lakes, rivers and mountains of all nations of the world.

Rajniti(politics) is comprised of the words - "Raj" and "niti" . "Raj" represents Raja(King). Rajahas its root in the word Rajayoga(Kriyayoga) ."Neeti" refers to the rules and laws essentially prescribed in the Science of Rajayoga. Guru Vasist, Guru Vishwamitra, Incarnation of Vishnu - Lord Ram & Lord Krishna, Mahaveer Swami, Gautam Buddha, Maharshi Patanjali, Saint Kabir, Guru Nanak Dev and Yogiraj Lahiri Mahasaya taught the Science of Rajayoga to all human beings who were ready. The knowers of Rajayogawere known as Rajas(Kings).

RajayogaScience explains that when one attains the state of Yoga, one joyfully performs all duties to provide perfect service to all like a Raja(King) . A Raja(King) is not illusioned by dualities such as joy and sorrow, profit and gain, sin and virtue, fame and disgrace etc. as experienced by an ordinary person. The life of a Raja is filled with perceptions of true love, Omniscient knowledge, eternal peace, Immortality and Omnipresence each moment. Generally, common people are not able to understand the actions of a Rajaand even when they try to, they often reach to a wrong conclusion. The common understanding is that that Rajas like Lord Ram and Lord Krishna lived a most difficult and sorrowful life. This is not true. Lord Ram and Lord Krishna were able to perform all work very easily with no stress and demonstrated success in all walks of life. They lived a life fully saturated with eternal peace and bliss. They did not ever experience sensory joy or sorrow at any time.

When a person who has attained the state of Yoga experiences oneself as Raja, then that person becomes most capable to provide protection and guidance, happiness and all the necessary facilities to all the creations of the nation. The citizens of the nation will then live a life free of fear and deficits. Today, it is important for everyone to understand the true meaning of Rajawhose meaning has been distorted. As the light of Kriyayoga is lit in each home, humanity will select the true Rajawho will be most successful to create an affluent nation.

In ancient human civilization, the personal living and lodging requirements and expenses of a true Rajawas minimal. As well, the daily expenses of all those persons who were in legislature, judiciary and administration were less than that of an ordinary person. In addition, those persons who are intelligent and wise are free from physical ailments and mental inharmonies.Today, there is an essential nseed to select the correct individuals as Rajas-- those who will be able to provide proper protection and facilities to humans, animals, plants, ponds, lakes, rivers, mountains and oceans of the nation.

The understanding of all people has to be increased in order to select a true Raja. This is however difficult, given the absence of a real education system that can increase one's understanding quickly. The traditional concept that an intelligent person is one who can reproduce matter that is heard or read, in speech and writing perfectly, is incorrect. Observe the function of a computer, a cell phone, mp3 player, and tape recorder. All these electronic devices can re-write and re-produce all matters without any mistake. In fact, they can work far better than human beings in this aspect. The intelligence and wisdom of human beings can be measured correctly through the advancement of research in various fields. In other words, an intelligent person is one who is engaged in continuous research and perceives ever-new joy while being on the path to seek Infinite knowledge and power within self, all humanity and all creations of the Cosmos.